भारत का 1991 संकट और आरबीआई गवर्नर की भूमिका

दिसंबर 1990 से दिसंबर 1992 तक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले आईएएस अधिकारी एस. वेंकिटरमनन का हाल ही में निधन हो गया। दो कार्यक्रम जिनमें उन्होंने भाग लिया था, रिकार्ड करने योग्य हैं। दोनों उन्हें एक ऐसे राजनेता के रूप में दिखाते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसके लिए वह याद किए जाने के पात्र हैं।

शुरुआत

1990 के अंत में, भारत को भुगतान संतुलन के गंभीर तनाव का सामना करना पड़ा। सद्दाम हुसैन द्वारा कुवैत पर आक्रमण के बाद आवक प्रेषण में कमी और तेल की कीमत में वृद्धि के कारण ऐसा हुआ था। भुगतान संतुलन के चालू खाते पर दोहरी मार पड़ी, प्राप्तियों में कमी आई और आयात के मूल्य में वृद्धि हुई। 1990-91 में चालू खाता घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत हो गया, जो दो दशकों में अब तक का उच्चतम स्तर है। ऐसी अटकलें थीं कि भारत अपने बाह्य भुगतान दायित्वों पर चूक करेगा। यह वह क्षण था जब श्री वेंकटरमणन के नेतृत्व में आरबीआई ने एक उत्कृष्ट भूमिका निभाई, जिसके परिणामस्वरूप कठिन मुद्रा ऋण के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंकों को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। इन पहलों और उनके महत्व का विवरण आरबीआई के आधिकारिक इतिहास में दिया गया है, "अप्रैल 1991 में, सरकार ने तस्करों से जब्त किए गए 20 टन सोने की बिक्री (पुनर्खरीद विकल्प के साथ) के माध्यम से यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड से 200.0 मिलियन डॉलर जुटाए। (एसआईसी)। फिर, जुलाई 1991 में, भारत ने 405.0 मिलियन डॉलर जुटाने के लिए बैंक ऑफ इंग्लैंड को 47 टन सोना भेजा। इस कार्रवाई से देश को अपने अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं और ऋणदाताओं को भुगतान करने में मदद मिली, हालांकि यह देश को संकट से पूरी तरह मुक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था। देश के सोने को गिरवी रखने के कार्य, जिसमें इसे विदेशों में ले जाना शामिल था, का भारत में कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया था। यह केवल संसार की अज्ञानता को प्रकट करता है। आरबीआई के लिए डिफॉल्ट से बचने के लिए अपने सोने का इस्तेमाल करना साहस का काम था। सचमुच, यह सबसे चतुर आर्थिक प्रबंधन था। केवल यह याद रखने की जरूरत है कि युद्धाभ्यास के व्यावहारिक मूल्य को पहचानने के लिए भारत अपना लगभग 80 प्रतिशत तेल आयात करता है। डिफॉल्ट से अपने आयात के वित्तपोषण के लिए वैश्विक ऋण बाजारों तक भारत की पहुंच सीमित हो जाती, यदि भविष्य में इसकी निर्यात आय कम हो जाती। भारत के स्वर्ण भंडार की बिक्री और गिरवी के साथ, भुगतान संकट में राहत की गुंजाइश पैदा हो गई थी।

आर्थिक सुधार

अंतर्राष्ट्रीय ऋण जुटाने के अपने प्रयासों से पहले, आरबीआई ने आयात संपीड़न का एक कार्यक्रम शुरू किया था, जिसे मुख्य रूप से आयात पर नकद मार्जिन बढ़ाकर लागू किया गया था। हालाँकि यह श्री वेंकटरमणन के राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण करने से पहले ही शुरू हो गया था, यह उनके अधीन था कि नीति ने अधिक बल प्राप्त किया। अक्टूबर 1990 और अप्रैल 1991 के बीच नकद मार्जिन में चार गुना बढ़ोतरी की गई थी। आयात की लागत बढ़ाने वाले पूरक उपायों को भी लागू किया गया था, साथ ही उन पर लगाम लगाने के लिए कड़े प्रयास किए गए थे। यह रणनीति विजेता साबित हुई, और चालू खाता घाटा 1990-91 में 3 प्रतिशत के उच्चतम स्तर से 1991-92 में सकल घरेलू उत्पाद का मात्र .3 प्रतिशत हो गया। इससे भारत के गैर-ऋण भुगतान के वित्तपोषण के लिए विदेशी मुद्रा जुटाने की आवश्यकता लगभग समाप्त हो गई। हालाँकि नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार को 1991 के मध्य में सत्ता संभालनी थी और लंबी अवधि में भुगतान संतुलन में सुधार के लिए रुपये के अवमूल्यन सहित कई कदम उठाने थे, लेकिन यह मानने का कारण है कि संतुलन में तत्काल सुधार होगा भुगतान में कमी के लिए मुख्य रूप से आरबीआई द्वारा लगाए गए आयात दबाव को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह डेटा द्वारा निहित है, जो दर्शाता है कि 1991-92 में आयात में काफी कमी आई थी, लेकिन निर्यात में वृद्धि नहीं हुई, लेकिन उनमें थोड़ी गिरावट आई। आरबीआई के इस अवधि के आधिकारिक इतिहास में कहा गया है, ष्एक महत्वपूर्ण समय में और बीओपी संकट के बीच, गवर्नर श्री एस वेंकटरमणन के नेतृत्व में रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य देश को संकट से उबारना था। जल। इसका निष्कर्ष यह है कि संकट का ष्सफलतापूर्वक समाधानष हो गया। हालाँकि, इसके बाद हुए आर्थिक सुधारों ने उस समय जनता का ध्यान आकर्षित किया, और यह समझ में भी आता है। डॉ. मनमोहन सिंह और उनकी टीम ने आर्थिक नीति व्यवस्था के साहसिक पुनर्गठन से बड़ी सफलता हासिल की है। एक बार भुगतान संतुलन का संकट बीत जाने के बाद, इसके वास्तुकारों को भुला दिया गया और भारत की

अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और वित्तीय साख की उनकी वीरतापूर्ण रक्षा को सार्वजनिक क्षेत्र में गुमनाम छोड़ दिया गया। और, गवर्नर वेंक. टरमणन के लिए, उनके कार्यकाल का अंत आरबीआई के आधिकारिक इतिहास के अनुसार ष्अप्रैल 1992 से प्रतिभूतियों के लेनदेन में अप्रत्याशित अनियमितताओं से संबंधित मुद्दोंष के कारण कम गौरवशाली नहीं था, जिसे जनता हर्षद मेहता के नाम से जानती है। घोटालाष।

उल्लेखनीय खुलापन

अंततः, काम पर श्री वेंकटरमणन को देखने का सौभाग्य पाकर, मुझे अपना अनुभव बताना चाहिए। 1991 के मध्य में किसी समय, मुझे उनसे एक पत्र मिला जिसमें कहा गया था कि आरबीआई ने मौद्रिक नीति के संचालन से संबंधित विषय पर मेरे एक लेख पर ध्यान दिया है, और वह व्यक्तिगत रूप से मेरी बात सुनकर प्रसन्न होगा। इसने एक उल्लेखनीय खुलेपन का प्रदर्शन किया, क्योंकि मैं न केवल पेशेवर रूप से अज्ञात था, बल्कि मेरा पेपर आरबीआई से निकले शोध की भी आलोचना करता था। इसके तुरंत बाद एक अनुवर्ती कार्रवाई होनी थी, जब उसी वर्ष सितंबर में मुझे भुगतान संतुलन संकट से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर गवर्नर से मिलने के लिए 20 से अधिक अर्थशास्त्रियों के साथ आमंत्रित किया गया था। उल्लेखनीय रूप से, भारतीय अर्थव्यवस्था पर हर तरह की राय, इसके भूगोल का उल्लेख न करें, उस दिन मेज पर प्रस्तुत की गई थी। लेकिन जो बात अधिक प्रभावशाली थी वह यह थी कि राज्यपाल ने प्रत्येक प्रस्तुति पर प्रतिक्रिया दी।

इसलिए, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ जब बाद में मैंने आरबीआई के साथ आईएमएफ की बातचीत के बारे में जानकारी रखने वालों को यह कहते हुए सुना कि श्री वेंकटरमणन भारत में स्थित अर्थशास्त्रियों द्वारा किए गए शोध के साथ अपने तर्कों को पेश करने में जल्दबाजी करेंगे। संभवतः, यह विश्वास था कि किसी देश को अपने बौद्धिक संसाधनों पर भरोसा करना चाहिए जिसने उन्हें आरबीआई के भीतर विकास अनुसंधान समूह की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। इसका उद्देश्य स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों को भारत के केंद्रीय बैंक तक ले जाना था ताकि इसके कर्मचारियों और बाहर के हितधारकों के बीच पेशेवर बातचीत हो सके। हालाँकि, इसमें वह पूरी तरह सफल नहीं हो सके। आज, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के संघर्ष से पता चलता है कि वह शायद यह समझने के बजाय कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, अर्थशास्त्र में वर्तमान रूढ़िवाद का पालन करने के लिए अधिक उत्सुक है।

प्रारंभिक परीक्षा संभावित प्रश्न (Prelims Expected Question)

प्रश्न : भारत में 1991 के आर्थिक संकट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 1990-91 में चालू खाता घाटा बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत हो गया था।
2. उस समय भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर मनमोहन सिंह थे।

उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements in the context of the economic crisis of 1991 in India:

1. In 1990-91, the current account deficit increased to 3 percent of GDP.
2. At that time the Governor of Reserve Bank of India was Manmohan Singh.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 & 2
(d) Neither 1 nor 2

उत्तर : C

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न: 1991 का आर्थिक संकट क्या था?केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस संकट को हल करने में क्या भूमिका निभाई थी?

उत्तर का दृष्टिकोण :

- उत्तर के पहले भाग में 1991 का आर्थिक संकट की विस्तार से चर्चा करें।
- दूसरे भाग में इस संकट को हल करने में केंद्रीय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका की चर्चा करें।
- अंत में सुझाव देते हुए निष्कर्ष दें।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।